

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक,  
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,  
30प्र0, लखनऊ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2019

विषय:- राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों द्वारा विभिन्न फसलों पर क्राप-कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु अनुमन्य दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 को सम्बोधित आपके पत्रांक-एस-1276/2018-19 दिनांक 20 अगस्त, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-499/12-5-2014-32/90टी0सी0 दिनांक 04.09.2014 को अतिक्रमित करते हुए राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों को विभिन्न फसलों पर क्राप-कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु रू0 260.00 प्रति क्राप-कटिंग प्रयोग दर पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

- |   |            |
|---|------------|
| (1) मजदूरी के मद में  | रू0 80.00  |
| (2) मानदेय के मद में  | रू0 80.00  |
| (राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों, जिनके द्वारा क्राप-कटिंग करायी जाये) |            |
| (3) क्षतिपूर्ति (प्रतिकर भत्ता) के मद में                         | रू0 100.00 |

.....  
कुल योग- रू0 260.00  
.....

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-03कृषि आकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

कृपया प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
अमित मोहन प्रसाद  
प्रमुख सचिव।

**संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 11.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-2, 30प्र0 शासन।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।